आरोप

तौल में हेराफेरी कर किसानों से तय सीमा से ज्यादा धान वसूला जा रहा, बम्हनी-मवई के खरीदी केन्द्रों पर गंभीर आरोप, प्रशासन मौन

धान उपार्जन केन्द्रों में खुलेआम चल रही मनमानी

बम्हनी बंजर, नवभारत। जिले में संचालित धान उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के साथ की जा रही मनमानी अब खुलकर सामने आने लगी है। बम्हनी बंजर और मवई क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों पर तय मानक से अधिक धान की तौल कर खरीदी किए जाने के आरोप किसानों ने लगाए हैं।

बताया जाता है कि मामला सामने आने के बाद किसानों में आक्रोश है और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।

तय 40 .500 के बजाय 40 .900 किलो की तौल

नगर परिषद बम्हनी बंजर स्थित धान उपार्जन केन्द्र क्रमांक-1 में गुरुवार को ग्राम बिचुआ से पहुंचे किसानों के साथ तौल में हेराफेरी किए जाने का आरोप लगाया। किसानों संजय और दीनू ने बताया कि वे जब धान विक्रय करने केन्द्र पहुंचे, तो कर्मचारियों ने तय 40.500 किलोग्राम के बजाय 40.900 किलोग्राम तक धान की तौल कर ली। किसानों का कहना है कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो खरीदी प्रभारी ने उनकी एक नहीं सुनी और मनमानी पर अड़ा रहा। आरोप है कि यही स्थिति केन्द्र पर आने वाले लगभग सभी किसानों के साथ है, लेकिन अब तक इस अवैध वसूली पर कोई रोक नहीं लग पाई है। किसानों ने यह भी बताया कि धान खरीदी केन्द्र पर मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। बैठने, पीने के पानी और छांव जैसी व्यवस्थाएं नदारद हैं, जिससे किसानों को घंटों परेशान होना पड़ रहा है।

मवई में भी वही हाल, 41 किलो तक तौल

वनांचल क्षेत्र मवई के धान उपार्जन केन्द्र में भी इसी तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। यहां किसानों से प्रति बोरी 41 किलोग्राम से अधिक धान की तौल किए जाने के आरोप हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि कम पढ़े-लिखे और दूर-दराज से आने वाले किसान विरोध नहीं कर पाते, जिसका फायदा खरीदी प्रभारी उठा रहे हैं। यहां प्रभारी कांटा खराब होने की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह अवैध वसूली और बढ़ेगी। हालांकि जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है।

इनका कहना है

मंडला एसडीएम के साथ बम्हनी बंजर खरीदी केन्द्र में जांच की गई है। किसानों के सामने तौल कराया गया। गड़बड़ी नहीं मिली है। बारदाने की साइज गलत होने से भ्रम हुआ है। रेंडम जांच में औसत 40.600 ग्राम के आसपास ही रहा है। किसी बोरी में अधिक तो किसी में कम तौल मिली है। जांच के बाद किसान भी संतुष्ट रहे हैं। मवई में भी जांच के लिए अधिकारी पहुंचे हैं।

संत कुमार भलावी, जिला आपूर्ति अधिकारी

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कुसमी का पंचायत भवन

सरपंच की दबंगई, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले ग्रामीणों को जेल भेजने की धमकी

घुघरी, नवभारत। आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका ताजा उदाहरण जनपद पंचायत घुघरी की ग्राम पंचायत कुसमी में देखने को मिल रहा है। यहाँ निर्माणाधीन नवीन ग्राम पंचायत भवन तकनीकी धांधली और सरपंच की मनमानी का गवाह बन गया है। स्वीकृत नक्शे को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्य ने प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बताया गया कि पंचायत भवन के स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार भवन की मजबूती के लिए कुल 37 कॉलम (पिलर) बनाए जाने थे। लेकिन हैरानी की बात है कि मौके पर केवल 29 कॉलम ही खड़े किए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच भोला मरावी ने भ्रष्टाचार के चलते 8 मुख्य कॉलम गायब कर दिए हैं। बिना कॉलम के बन रहा यह भवन भविष्य में किसी बड़े हादसे को न्यौता दे सकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ग्रामीणों के साथ सरपंच का व्यवहार संदेहास्पद है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर किसी को आने नहीं दिया जाता। सवाल पूछने पर झूठी एफआईआर कराकर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। विरोध दबाने के लिए कुछ ग्रामीणों पर पहले ही फर्जी मामले दर्ज कराए जा चुके हैं।

जिम्मेदार दे रहे विरोधाभाषी बयान

इस मामले में विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। निर्माण देख रहे मैट गणेश यादव ने स्वीकार किया कि बाउंड्री वॉल के 8 कॉलम नहीं बनाए गए हैं। वहीं उपयंत्री डीपी अहिरवार का दावा है कि काम गुणवत्तापूर्ण है, लेकिन मौके से गायब 8 कॉलमों पर उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है।

बिना तराई एवं मिलावटी सामग्री का हो रहा उपयोग

ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण में मानक रेत के स्थान पर मिट्टी युक्त घटिया रेत का उपयोग हो रहा है। दीवारों पर पानी की तराई तक नहीं की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि बिना तराई किए ही 30 हजार रुपये का पानी टैंकर का फर्जी बिल निकाल लिया गया। ग्रामीण परशुराम बंजारा का आरोप है कि जब भी पंचायत का निर्माण कार्य शुरू होता है, सरपंच अपने घर का काम भी शुरू कर देता है। ग्रामीणों को संदेह है कि सरकारी सामग्री और कॉलम का उपयोग सरपंच अपने निजी हित में कर रहा है।

ग्रामीणों ने की मांग

ग्रामीण गंगाराम धुर्वे, पालन सिंह समेत ग्राम के अन्य जागरूक ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से मांग की है कि निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए और गायब कॉलमों के साथ गुणवत्ताविहीन कार्य करने वाले सरपंच व संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

बिनेका में 4 शराब तस्कर पर कार्रवाई

बिनैका। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम बिनेका कोन्ड्रा में घेराबंदी कर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त चार आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी अनुसार थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि ग्राम बिनेका में कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध शराब का विक्रय और भंडारण किया जा रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक शफीक खान के नेतृत्व में तत्काल एक विशेष टीम गठित की गई और ग्राम बिनेका में दबिश दी गई। पुलिस की रेड के दौरान मौके से कुल 32 लीटर अवैध देशी मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 हजार 380 रूपए आंकी गई है। इसके साथ ही शराब बनाने के उद्देश्य से रखे गए 12 डब्बों में भरा लगभग 70 किलोग्राम महुआ लाहन भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। अवैध शराब विक्रय के मामले में पुलिस ने चमन परते, 38 वर्ष, निवासी ग्राम बिनेका कोन्ड्रा, राजेन्द्र भारतीया, 42 वर्ष निवासी, सुरेश भारतीया, 42 वर्ष निवासी ग्राम बिनेका कोन्ड्रा, ललित पटेल, 55 वर्ष निवासी ग्राम बिनेका पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की जा रही कवायद

नारायणगंज सीएचसी में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिविर आयोजित

नारायणगंज। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नारायणगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक नैदानिक सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की गईं।

शिविर का मुख्य लक्ष्य प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना और ऐसी महिलाओं की पहचान करना है, जिनकी गर्भावस्था हाईरिस्क की श्रेणी में आती है। शिविर के दौरान अनुभवी चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं का शारीरिक परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक लैब सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं की आवश्यक जांचें की गईं, जिनमें मुख्य रूप से हिमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, एचआईवी, यूरिन प्रोटीन और एल्बुमिन की जांच शामिल थी। वर्तमान समय में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए, इस बार गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज की जांच प्रमुखता से की गई।

उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान अनिवार्य-नारायणगंज बीएमओ डॉ. अमृत लाल कोल ने शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रसव से पहले ही हाईरिस्क मामलों की पहचान हो जाती है। यदि किसी महिला में गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य जटिलताएं पाई जाती हैं, तो उन्हें उच्च जोखिम गर्भावस्था के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसी महिलाओं का प्रसव होने तक विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

हर माह की 9 व 25 तारीख को लगता है शिविर-सीएमएचओ डॉ. डीजे मोहंती ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने की 9 व 25 तारीख को यह शिविर आयोजित किया जाता है। यदि 9 व 25 तारीख को कोई शासकीय अवकाश होता है, तो अगले कार्य दिवस पर शिविर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यदि किसी महिला के गर्भाशय में कोई समस्या या भ्रूण में असामान्यता पाई जाती है, तो उसे तुरंत उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जिससे प्रसव के समय जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें।

नि:शुल्क सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील-शिविर में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि इस अभियान के तहत दी जाने वाली सभी सेवाएं, दवाइयां और जांचें पूरी तरह से नि:शुल्क हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शिविर के अंत में महिलाओं को पोषण आहार और प्रसव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा।

श्रीमद् भागवत के भक्ति रस में डूबा ग्राम देवरी

नारायणगंज। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणगंज के ग्राम देवरी में इन दिनों श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वर गूंज रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों और महिला मंडल के विशेष सहयोग से आयोजित इस नौ दिवसीय ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन आध्यात्मिक उत्साह अपने चरम पर रहा। कथा व्यास पंडित कृष्णगोपाल पाण्डेय ने प्रभु श्री कृष्ण की मोहक बाल लीलाओं का वर्णन कर पंडाल में मौजूद भक्तों को भाव-विभोर कर दिया।

कथा व्यास ने पांचवें दिन की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण की उन लीलाओं से की जो उन्होंने गोकुल के गोप-गोपियों को आनंद देने के लिए की थीं। कथा व्यास पंडित कृष्णगोपाल पाण्डेय ने बताया कि भगवान कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कान्हा केवल माखन नहीं चुराते थे, बल्कि वे अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते थे। गोपियों के घरों में मटकियां फोड़ना और सखाओं के साथ मिलकर माखन बांटकर खाना, यह संदेश देता है कि ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। जब माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांधा, तो भगवान ने अपनी इस लीला से दामोदर नाम पाया और यमलार्जुन का उद्धार किया। कथा के दौरान आगे यमुना नदी को विषमुक्त करने के प्रसंग का विशेष वर्णन किया गया। कथा व्यास पंडित कृष्णगोपाल पाण्डेय ने बताया कि यह प्रसंग मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार और क्रोध रूपी विष को समाप्त करने का प्रतीक है।

छतरपुर पंचायत में जांच के दौरान हंगामा, रिकॉर्ड गायब होने पर लौटी टीम

कैशबुक अधूरी होने पर बिफरे ग्रामीण, भ्रष्टाचार छुपाने के लगे आरोप

घुघरी। जनपद पंचायत घुघरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छतरपुर में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने पहुंची टीम के सामने पंचायत का कच्चा चिट्ठा खुल गया। सचिव द्वारा पिछले दो वर्षों का वित्तीय रिकॉर्ड तैयार न होने के कारण जांच दल को अपनी कार्रवाई बीच में ही रोककर वापस लौटना पड़ा। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत छतरपुर में वर्ष 2022 से 2025 के बीच पंच परमेश्वर योजना और नल-जल योजना सहित अन्य विकास कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जनपद पंचायत घुघरी से एक उच्च स्तरीय जांच दल दोपहर 3 बजे पंचायत भवन पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और शिकायतकर्ता भी साक्ष्यों के साथ मौजूद थे। जांच समिति ने जब ग्रामीणों की मौजूदगी में एक-एक कर शिकायतों की समीक्षा शुरू की और वित्तीय पारदर्शिता की जांच के लिए कैशबुक मांगी, तो चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। पंचायत सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 और आगामी 2025-26 की कैशबुक अब तक तैयार ही नहीं की गई थी। बिना कैशबुक और आधिकारिक वाउचर के यह पता लगाना असंभव था कि सरकारी राशि का भुगतान कहाँ और कैसे किया गया। रिकॉर्ड के अभाव में जांच टीम ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बैरंग लौट गई।

भ्रष्टाचार छुपाने के लिए गायब किया रिकॉर्ड-जांच पूरी न होने से मौके पर मौजूद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामवासियों का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार छुपाने सचिव ने जान बूझकर रिकॉर्ड अधूरा रखा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि लापरवाह सचिव पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जांच दल के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्ड के अभाव में कार्य रोक दिया है और इस पूरी अव्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट जनपद सीईओ और जिला प्रशासन को भेजी जा रही है।

मान्यता रद्द होने के बाद भी ऑक्सफोर्ड स्कूल का संचालन जारी

नैनपुर में शिक्षा माफिया बेखौफ, पोर्टल से नाम कटे, अभिभावकों को अंधेरे में रख चला रहे कक्षाएं

नैनपुर। नगर में शिक्षा को व्यापार बनाने वाले शिक्षा माफिया इन दिनों सक्रिय हैं। ताजा मामला नैनपुर वार्ड क्रमांक 9 में संचालित अशासकीय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहाँ विभाग द्वारा मान्यता समाप्त किए जाने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पोर्टल पर सभी बच्चों की टीसी जारी की जा चुकी है, लेकिन पालक इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। जानकारी अनुसार अनिवार्य अहर्ताओं को पूरा न कर पाने के कारण इस विद्यालय की मान्यता मार्च 2025 में ही समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद प्रबंधन ने अक्टूबर 2025 में पुन: मान्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन 12 नवंबर 2025 को जिला और जनपद शिक्षा केंद्र की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के बाद इसे फिर से निरस्त कर दिया। स्पष्ट आदेश के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने न तो स्कूल बंद किया और न ही पालकों को इसकी सूचना दी। शिकायत मिलने पर 7 जनवरी को जनपद शिक्षा केंद्र नैनपुर की टीम पुन: विद्यालय पहुंची। बीआरसी बिजेंद्रधर द्विवेदी, जन शिक्षक दीपक देहले और दिनेश झारिया ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय संचालन के साक्ष्य जुटाए। टीम ने बाल्कान रजिस्टर को जब्त कर अभिभावकों की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई की है।

वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की दिशा में पहल

कलेक्टर ने किया ग्राम बीजाडांडी का पैदल भ्रमण

बीजाडांडी। वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने विकासखंड मंडला के बीजाडांडी ग्राम का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद किया और उनकी समस्याओं, जरूरतों व अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने ग्रामीणों को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शासन का उद्देश्य वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर वहां निवासरत परिवारों को भूमि अधिकार, बुनियादी सुविधाएं और शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ दिलाना है। उन्होंने ग्रामीणों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली एवं पेयजल जैसी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने से जुड़े सभी आवश्यक प्रस्ताव, दस्तावेज एवं प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने से ग्रामीणों को भूमि स्वामित्व, पट्टे, आवास, पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य शासकीय सुविधाओं में सुविधा होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों के हितों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, सीईओ प्रतिमा शुक्ला, सरपंच, सचिव सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।

श्रमदान के माध्यम से बोरी बंधान कर सहेजा जा रहा है जल

नारायणगंज में जन अभियान परिषद की अनूठी पहल

नारायणगंज, नवभारत। जल ही जीवन है और इसे सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी संदेश के साथ मप्र जन अभियान परिषद विकासखंड नारायणगंज के तत्वावधान में ग्राम पंचायत शाहा के नाला में बोरी बंधान का कार्य संपन्न हुआ। स्वैच्छिकता और सामूहिकता की मिसाल पेश करते हुए ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने मिलकर 90 बोरियों का बंधान बनाया, जिससे वर्षा जल को रोककर भू-जल स्तर को बढ़ाया जा सके।

आयोजित कार्यक्रम ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति शाहा, नवांकुर संस्था प्रगति जन कल्याण समिति और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत इसमें समाज कार्य बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू के छात्र-छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर श्रमदान किया।

नदी-नालों का संरक्षण आज की आवश्यकता

बोरी बंधान के बाद आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला समन्वयक राजेंद्र चौधरी ने गिरते भू-जल स्तर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा आज बड़ी नदियां भी गर्मी में सूख रही हैं, इसलिए उनके कैचमेंट एरिया यानी छोटे नदी-नालों को बचाना अनिवार्य है। विकासखंड समन्वयक संतोष कुमार झारिया ने प्रस्फुटन समिति और नवांकुर संस्थाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बोरी बंधान, सोख्ता गड्ढे और जल स्रोतों की सफाई के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान के साथ संगोष्ठी और चौपाल का आयोजन किया जा रहा है।

आमजनों को जल संरक्षण की दिलाई शपथ

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को जल की बर्बादी रोकने और जल संवर्धन के लिए सामूहिक शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर शाहा ग्राम पंचायत के सरपंच, प्रस्फुटन समिति के रेवत वरकडे, परामर्शदाता राकेश अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, सुरेश सोनी, इंद्रा उइके, नवांकुर संस्था प्रमुख कमलेश पावले, देवलता उइके, मिथलेश कुशराम, महेंद्र उइके, सुशीला वरकड़े सुमित , सुनील, पलक रजक, अंजली बर्मन एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे। उपस्थित सभी जनों को श्रमदान कर समाज को जल बचाने के प्रति जागरूक किया।